

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2199
उत्तर देने की तारीख-09/12/2024

श्रीअन्न सर्वेक्षण

†2199. श्री कीर्ति आज़ाद:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा लाभार्थियों को मिलने वाले पोषण और उनके स्वास्थ्य पर श्रीअन्न को शामिल करने के प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई श्रीअन्न सर्वेक्षण किया जा रहा है/कराने की योजना बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या श्रीअन्न को प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उन सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने अपनी वार्षिक कार्य योजना और बजट में श्रीअन्न को शामिल करने का प्रस्ताव दिया है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जयन्त चौधरी)

(क) और (ख): जी नहीं।

(ग) से (ङ): प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझेदारी में कार्यान्वित की जाने वाली सबसे प्रमुख अधिकार आधारित केंद्र प्रायोजित योजनाओं में से एक है। पात्र बच्चों को पका हुआ गर्म और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने की समग्र जिम्मेदारी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र निर्धारित पोषण सामग्री को पूरा करने के लिए अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार अपनी व्यंजन-सूची तय करते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को "इंटरनेशनल

इयर ऑफ मिलेट्स” घोषित किया है। तदनुसार, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को विभिन्न चिह्नित गतिविधियों जैसे वाद-विवाद प्रतियोगिता, रैलियों, नुक्कड़ नाटक, विशेष स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) की बैठकों और स्वयंप्रभा चैनलों पर श्री अन्न के उपयोग संबंधी विशेष कार्यक्रमों आदि के माध्यम से श्रीअन्न से होने वाले स्वास्थ्य लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए परामर्शिका जारी की गई थी।

सभी राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सलाह दी गई है कि वे सप्ताह में कम से कम एक बार श्रीअन्न आधारित व्यंजन शुरू करने की संभावना पर विचार करें। श्रीअन्न आधारित व्यंजनों को लोकप्रिय बनाने के लिए रसोइया-सह-सहायकों के बीच पाककला प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सुझाव दिया गया है। तदनुसार, कई राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने श्रीअन्न आधारित व्यंजनों को बढ़ावा देने के लिए योजना के तहत काम करने वाले रसोइये-सह-सहायकों के बीच राज्य/जिला स्तर पर पाककला प्रतियोगिताएं आयोजित की हैं। यह भी सुझाव दिया गया है कि श्रीअन्न के गुणों के विषय में जागरूकता पैदा करने के लिए छोटे-छोटे वीडियो तैयार किए जाएं और उन्हें स्कूलों में प्रदर्शित किया जाए तथा स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) की बैठकों और अभिभावक-शिक्षक बैठकों के दौरान श्रीअन्न के उपभोग पर चर्चा की जाए।

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह भी सलाह दी गई कि वे अपनी वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपीएंडबी) में श्रीअन्न की आवश्यकता को शामिल करें। कई राज्य अतिरिक्त खाद्य पदार्थ के रूप में श्रीअन्न उपलब्ध करा रहे हैं, जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना राज्य अतिरिक्त श्रीअन्न खाद्य पदार्थ के रूप में रागी जावा उपलब्ध करा रहे हैं।
